

भारतीय अर्थव्यवस्था : कतिपय परिदृश्य* वाई.वी. रेड्डी

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अपने कुछेक विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए पीटर्सन इंस्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स द्वारा आमंत्रित किए जाने पर मैं अत्यधिक गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। यह बैठक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और उसके भविष्य के प्रति हाल ही में देखने में आई बढ़ती रुचि और विश्वास का प्रतिबिंबन करती है। आज मैं यह कहना चाहता हूँ कि 1947 में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र रूप से यथोचित स्थिरता के साथ ही क्रमिक रूप से स्वतः त्वरणशील विकास के पथ पर अग्रसर है। 21वीं सदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य-निष्पादन तथा उसके प्रति विश्वास के स्तर में उल्लेखनीय त्वरण परिलक्षित होता है। हाल ही की विश्वव्यापी अनिश्चितताओं के बावजूद अल्पकालिक संभावनाएं, कुल मिलाकर, भारत के लिए हितकर बनी हुई हैं। मध्यकालिक दृष्टि से कतिपय चुनौतियां और अवसर विद्यमान हैं। अतएव सार्वजनिक नीति में न केवल वैश्विक समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरने, अपितु और अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से, भारत में रहने वाले विशेष रूप से विविध पृष्ठभूमियों वाले लाखों गरीब और अल्प-सुविधा प्राप्त लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उद्देश्य से इन्हीं पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करना होगा।

I. स्वाधीनता प्राप्ति से लेकर नयी सहस्राब्दि तक स्वतः त्वरणशील संवृद्धि

स्वाधीनता के पहले, 20वीं सदी के पहले पांच दशकों (1900-01 से लेकर 1946-47 तक) के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का औसत वार्षिक वृद्धि-निष्पादन औसतन 0.9 प्रतिशत के रूप में निराशाजनक था। 1950 वाले दशक के प्रारंभिक दिनों में नियोजित विकास प्रक्रिया की शुरुआत से सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में स्वतः त्वरणशील प्रवृत्ति परिलक्षित हुई तथा वह 1990 वाले दशक में लगभग 6.0 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच गई। इस चरण में अपवाद रहे, 1970 के दशक में वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत हो जाना तथा

* 17 अक्टूबर, 2007 को पीटर्सन इंस्टिट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकॉनॉमिक्स, वाशिंगटन डी.सी. में डॉ. वई.वी. रेड्डी, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया व्याख्यान।

1991-92¹ वाला संकट का वर्ष, जब वृद्धि दर घट कर 1.4 प्रतिशत पर आ गई थी। भारत में मुद्रास्फीति का रिकार्ड संतोषजनक रहा है। स्वाधीनता के समय से ही थोक मूल्य की दृष्टि से मुद्रास्फीति, औसत आधार पर, पचास वर्षों में से 5 वर्षों में 15 प्रतिशत से अधिक रही। पचास में से छत्तीस वर्षों में मुद्रास्फीति एक अंकीय रही तथा अधिकांश अवसरों पर मुद्रास्फीति की अधिकता ईंधन और खाद्यान्न की कीमतों में तीव्र वृद्धि जैसे बाहरी और घरेलू आघातों के कारण रही।

नयी सहस्राब्दि में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की दर में और अधिक बढ़ोत्तरी हुई तथा वह 2000-01 से 2006-07 तक के सात वर्षों की अवधि में औसतन 6.9 प्रतिशत रही, जबकि विगत चार वर्षों (2003-04 से लेकर 2006-07 तक) में वृद्धि दर का औसत 8.6 प्रतिशत था। वर्ष 2005-06 और 2006-07 में यह क्रमशः 9.0 प्रतिशत तथा 9.4 प्रतिशत की दर से और अधिक बढ़ी। इस चरण में भी, वर्ष 2002-03 के एक वर्ष के दौरान देश के कतिपय भागों में सूखे की स्थिति के कारण, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण गिरावट आ गई, वृद्धि दर घट कर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। इस अवधि में वृद्धि दर में हुई बढ़ोत्तरी के साथ ही विशेषतः उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव में महत्वपूर्ण कमी आई। इस बात को भी ध्यान में रखना उपयोगी होगा कि भारत में वृद्धि की प्रक्रिया मुख्यतः घरेलू उपभोग द्वारा संचालित होती है, जिसका समग्र मांग में औसतन लगभग दो-तिहाई अंशदान रहा।

हाल के वर्षों में आर्थिक गतिविधि के सुदृढ़ीकरण की सकल घरेलू निवेश दर, जो वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 24.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 33.8 प्रतिशत हो गई तथा घरेलू बचत दर, जो 2000-01 में 23.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005-06 में 32.4 प्रतिशत हो गई, में हुई निरंतर वृद्धि से समर्थन प्राप्त हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस अवधि के दौरान

¹ भारत में, राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है।

हुए निवेशों में से 90 प्रतिशत से भी अधिक का वित्तीयन घरेलू बचतों से हुआ।

अर्थव्यवस्था में निवेश की दरों में हुई बढ़ोत्तरी के अनुक्रम में ही उत्पादकता और पूंजी के उपयोग की निपुणता में वृद्धि के साक्ष्य भी मौजूद हैं। भारत से संबंधित हाल ही के कुछेक अध्ययनों से पता चला है कि कुल घटक उत्पादकता (टीएफपी) में वृद्धि के संकेत प्राप्त हुए हैं। उदाहरण के तौर पर 2004 के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक कार्यपरक आलेख में रॉड्रिक्स और सुब्रमणियन इस बात का उल्लेख करते पाए जाते हैं कि ऐसा लगता है कि भारत ने अपेक्षाकृत संतुलित सुधारों से भारी मात्रा में उत्पादकता वृद्धि हासिल कर ली है।

जहां नयी सहस्राब्दि में वृद्धि दर में बढ़ोत्तरी हुई है वहीं मुद्रास्फीति की दर घटकर और भी कमतर स्तर पर आ गई है, जिससे मूल्य-स्थिरता सुनिश्चित हुई है। वर्ष 2000-01 से थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से आकलन किए जाने पर वार्षिक मुद्रास्फीति की दर, हाल ही की तेल की कीमतों में वृद्धि से संबंधित आघात के बावजूद, औसतन 5 प्रतिशत से कम रही है। नयी सहस्राब्दि में अंक-दर-अंक आधार पर दर्ज सर्वाधिक वार्षिक मुद्रास्फीति वर्ष 2002-03 (6.5 प्रतिशत) में उस समय थी, जब वृद्धि दर देश के कुछेक भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई थी। इससे भी अधिक निकटवर्ती दिनों में, जनवरी 2007 के अंत में मुख्यतः खाद्यान्न की कीमतों में बढ़ोत्तरी के कारण थोक मूल्य मुद्रास्फीति 6.7 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद 29 सितम्बर 2007 को समाप्त सप्ताह में घटकर 3.3 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।

सकल घरेलू उत्पाद में हुई अधिक वृद्धि के साथ ही निकटवर्ती वर्षों में मुद्रा आपूर्ति गैर-खाद्यान्न ऋणों की वृद्धि दर में भी बढ़ोत्तरी हुई है, जिससे मुख्यतः देश में पूंजी प्रवाह में बढ़ोत्तरी का प्रतिबिंबन होता है। इन घटनाओं के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में उत्पन्न अत्यधिक उबाल के संकेतों के प्रमाण पर सक्रिय बहस आरंभ हो गई, किन्तु

बाद में मुद्रास्फीति में आई कमी सहायक सिद्ध हुई है। यह कमी लाने में रिजर्व बैंक ने सामयिक और उपयुक्त मौद्रिक उपायों तथा उपभोक्ता वित्त, स्थावर संपदा, आवास एवं पूंजी बाजार एक्सपोजर जैसी बैंकिंग आस्तियों की चुनिंदा श्रेणियों की प्रावधानीकरण अपेक्षाओं एवं जोखिम भारों को बढ़ाने जैसे कुछेक विवेकसम्मत उपायों के माध्यम से योगदान किया। ये उपाय त्वरित ऋण वृद्धि एवं बैंक के प्रभुत्व वाले वित्तीय क्षेत्र में बैंकों के तुलन पत्रों पर आस्तियों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ावों के संभाव्य प्रभाव जैसे मुद्दों के विशिष्ट रूप से निराकरण के लिए आवश्यक थे।

केन्द्र और राज्यों के संयुक्त राजकोषीय घाटे के वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से घट कर वर्ष 2006-07 में 6.4 प्रतिशत हो जाने के फलस्वरूप देश में राजकोषीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ। हालांकि, केन्द्र और राज्यों का संयुक्त सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में 70 प्रतिशत से अधिक के रूप में अधिक बना हुआ है।

वर्ष 2000-01 से वर्ष 2003-04 तक की अवधि में कुछेक वर्षों के मामूली अधिशेष के उपरांत चालू खाते के घाटे के अत्यधिक संतुलित रखे जाने के फलस्वरूप भारत का विदेशी क्षेत्र पुनरुज्जीवित हो गया है। निर्यात और आयात, दोनों ही का मूल्य अमेरिकी डॉलर में मूल्य की दृष्टि से वर्ष 2000-01 के मुकाबले बढ़कर वर्ष 2006-07 में तीन गुना हो गया है तथा चालू खाते का घाटा सात में से चार वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के 1.1 प्रतिशत की दर पर संतुलित रहा, जबकि शेष वर्षों में इसमें अधिशेष की स्थिति रही। सामानों एवं सेवाओं के व्यापार मूल्य के वर्ष 2000-01 में सकल घरेलू उत्पाद के 29.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006-07 में 49.2 प्रतिशत हो जाने के फलस्वरूप भारत वस्तुतः एक अत्यधिक खुली अर्थव्यवस्था वाला देश हो गया है। सुदृढ़ पूंजी प्रवाह के कारण विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधि में उपचय हुआ है, जो 5 अक्टूबर 2007 के दिन 251.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच कर इस समय विदेशी ऋण (जून

2007 के अंत में 165.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक है। अधिकांश अवधि में विनिमय दर में सांकेतिक और वास्तविक दोनों ही दृष्टियों से दुतरफा हलचल परिलक्षित हुई है।

ढांचागत समायोजन और आर्थिक सुधार कार्यक्रम के अंग के रूप में 1990 वाले दशक के प्रारंभिक दिनों में लागू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव हुआ। सुधारात्मक उपायों को पारस्परिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से सुधारात्मक प्रक्रिया को परामर्शात्मक एवं क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम परंपराएं अपनाते हुए आगे बढ़ाया गया। जहाँ मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि लाना था, वहीं सहवर्ती ध्येय नए बाजारोन्मुख परिवेश को स्थायित्व प्रदान करना था।

वित्तीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण नीतिगत उपाय आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अपेक्षा जैसे सांविधिक पूर्व-क्रय में चरणबद्ध रूप से कमी लाने तथा चुनिंदा वर्ग को छोड़कर जमाराशियों और अग्रिमों पर ब्याज दरों के अविनियमन से संबंधित हैं। रिजर्व बैंक ने प्रभावी पर्यवेक्षण द्वारा समर्थित एक समर्थक विनियामक ढांचे और विधिक, प्रौद्योगिकीय एवं संस्थागत आधारभूत संरचना स्थापित करने के प्रयास किए हैं। पूंजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण से संबंधित विनियामक मानदण्ड क्रमिक रूप से अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्ट परंपराओं के साथ अभिसरण की दिशा में प्रवृत्त हुए हैं। बासेल II पूंजी पर्याप्तता ढांचे को मार्च 2008 से चरणबद्ध रीति से कार्यान्वित किया जा रहा है। बैंकिंग संस्थाओं के स्वामित्व का विविधीकरण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयरधारिता के माध्यम से संभव बनाया गया है तथा वित्तीय क्षेत्र में निजी एवं विदेशी संस्थाओं और विदेशी पूंजी के प्रवेश के साथ ही प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार में गैर-विघटनकारी एवं किफायती विधि वाली प्रतिस्पर्धा, विनियमन एवं स्वामित्व का व्यापक पुनर्विन्यास शामिल है।

1990 वाले दशक के प्रारंभिक दिनों में लागू किए गए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से वित्तीय बाजारों के विकास को सुदृढ़ प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। रिजर्व बैंक एक कुशल एवं सुदृढ़ भुगतान एवं निपटान प्रणाली के साथ-साथ मुद्रा, सरकारी प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा बाजारों का विकास करने, उसे व्यापकता एवं गहनता प्रदान करने के कार्य में निरंतर सक्रिय रहा। इस अवधि में इन वित्तीय बाजारों की क्षमता को उन्नत बनाने हेतु कई प्रकार के विनियामक एवं संस्थागत सुधार नियोजित विधि से लागू किए गए। इनमें बाजार के सूक्ष्म ढांचे के विकास, ढांचागत अवरोधों के निर्मूलन, नये प्रतिस्पर्धियों और लिखतों के प्रचलन एवं उनके विविधीकरण, वित्तीय आस्तियों के निर्बाध मूल्य निर्धारण, मात्रात्मक प्रतिबंधों में छूट, बेहतर विनियामक प्रणालियों, नयी प्रौद्योगिकी के प्रचलन, व्यापारिक आधारभूत सुविधा में सुधार, समाशोधन एवं निपटान परंपराओं तथा अधिकाधिक पारदर्शिता का समावेश था। कुल मिलाकर ईक्विटी बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार और सरकारी प्रतिभूति बाजार विश्वव्यापी उत्कृष्ट मानकों के अनुरूप हैं, जबकि एक स्वस्थ कॉर्पोरेट ऋण बाजार के शीघ्र विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है।

II. अल्पावधिक संभावनाएं

मौद्रिक नीति के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2007 के अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य में यह मानते हुए कि कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में और बढ़ोत्तरी नहीं होगी तथा किसी प्रकार का घरेलू और विदेशी आघात नहीं पहुंचेगा, वर्ष 2007-08 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के लगभग 8.5 प्रतिशत होने का अनुमान व्यक्त किया था। आगे की अवधि हेतु नीतिगत प्राथमिकता पूरी तरह से मूल्य-स्थिरता तथा स्फीतिकारक अपेक्षाओं को पूर्णतः नियंत्रित रखे जाने के पक्ष में है, जिसमें प्रयास यह होगा कि मुद्रास्फीति को 2007-08 में 5.0 प्रतिशत के आसपास तथा मध्यावधि में उसे 4.0-4.5 प्रतिशत की श्रेणी में

नियंत्रित रखा जाए। मौद्रिक नीति निर्धारण के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने वृद्धि और मुद्रास्फीति से संबंधित संभाव्यता के अनुरूप ही वर्ष 2007-08 के लिए मुद्रा आपूर्ति (एम³) की वृद्धि दर 17.0-17.5 प्रतिशत के आसपास तथा खाद्येतर ऋण के 24-25 होने का अनुमान लगाया है। मौद्रिक नीति में व्यक्त अपनी धारणा पर कायम रहते हुए रिजर्व बैंक ने 31 जुलाई 2007 को जारी अपने वार्षिक नीतिगत वक्तव्य की पहली तिमाही की समीक्षा में वित्तीय स्थिरता के महत्त्व को रेखांकित किया है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2007-08 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2007) में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2006-07 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च, 2007) के 9.1 प्रतिशत तथा पिछले वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून, 2006) के 9.6 प्रतिशत की तुलना में 9.3 प्रतिशत बढ़ा। वर्षानुवर्ष आधार पर थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति एक वर्ष पूर्व के 5.4 प्रतिशत से घटकर 29 सितम्बर 2007 को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.3 प्रतिशत हो गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (औद्योगिक कामगारों के लिए) पिछले वर्ष की इसी अवधि के 6.3 प्रतिशत के मुकाबले अगस्त 2007 में 7.3 प्रतिशत थी। 28 सितम्बर 2007 को व्यापक मुद्रा (एम³) आपूर्ति की वृद्धि वर्षानुवर्ष आधार पर 21.0 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष 19.0 प्रतिशत)। यद्यपि खाद्येतर ऋण वृद्धि तेज और व्यापक आधार वाली थी, वह 1 वर्ष पहले के 31.6 प्रतिशत से घटकर 28 सितम्बर 2007 को 22.1 प्रतिशत रह गई। जहाँ निर्यात में संवेग जारी रहा, वहीं आयात में तेजी से वृद्धि हुई, जिसके फलस्वरूप व्यापार घाटा पिछले वर्ष की इसी अवधि के 19.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर अप्रैल-अगस्त 2007 के दौरान 32.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस समय आरक्षित नकदी निधि अनुपात, जो रिजर्व बैंक के पास रखी गई अलाभकारी प्रारक्षित निधि होती है, 7.0 प्रतिशत की दर पर है, जबकि रेपो दर तथा

प्रत्यावर्ती रेपो दर क्रमशः 7.75 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत है।

वैश्विक घटनाओं से उद्भूत जोखिम, विशेषतः स्फीतिकारक दबावों, वित्तीय बाजारों द्वारा जोखिमों के मूल्य-पुनर्निर्धारण और कुछेक आस्ति वर्गों में गिरावट की संभाव्यता के रूप में निरंतर बने हुए हैं। अत्यधिक लीवरेजिंग के कारण वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुभेद्यता बढ़ गई है। चलनिधि की शर्तों में बहुत सारे परिवर्तन के कारण जोखिमों का मूल्यांकन दुरूह होता जा रहा है, जिसके साथ ही अनिश्चितता बढ़ रही है। विश्वव्यापी स्तर पर वित्तीय बाजारों और मौद्रिक नीति निरूपणों, दोनों ही के साथ जुड़े प्रवाहों को ध्यान में रखते हुए भारत इन घटनाओं से असंक्राम्य नहीं रह सकता। अब रिजर्व बैंक के समक्ष उपस्थित नीतिगत चुनौती है वर्तमान संक्रमण को इस प्रकार प्रबंधित करना कि उसे स्फीतिकारक दबावों को नियंत्रित रखकर वित्तीय स्थिरता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उच्चतर वृद्धि के मार्ग पर ले जाया जा सके। प्रसंगवश, रिजर्व बैंक में कार्यरत हम लोग इसीलिए अधिकाधिक सतर्कता बरत रहे हैं, ताकि हम विश्वव्यापी वित्तीय एवं मौद्रिक स्थितियों में विद्यमान अत्यधिक अनिश्चितताओं का समुचित ढंग से सामना करने में समर्थ हों।

हम 30 अक्टूबर 2007 को जारी की जाने वाली वार्षिक नीति की मध्यावधिक समीक्षा के एक अंग के रूप में विकासशील समाष्टि आर्थिक स्थितियों का विस्तृत मूल्यांकन प्रदान किए जाने की आशा करते हैं। मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति की 25 अक्टूबर 2007 को बैठक आयोजित हो रही है, जिससे हमेशा की भांति ही समीक्षा के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

III. मध्यावधिक चुनौतियां एवं संभावनाएं

भारत जैसी विशाल एवं बहुविध अर्थव्यवस्था के मामले में, जो कम प्रति व्यक्ति आय के कारण अत्यधिक अनिश्चित वैश्विक परिवेश में ढांचागत रूपांतर के क्रम से गुजर रही है, सार्वजनिक नीति की दृष्टि से कई प्रकार

की चुनौतियां मौजूद हैं। मैं कुछेक ऐसी चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक की अद्यतन वार्षिक रिपोर्ट, एक ऐसा प्रलेख जो इस विषय पर हमारे निदेशक मण्डल के लब्धप्रतिष्ठ सदस्यों के विचारों का प्रतिबिंबन करता है, में स्पष्ट किया गया है।

पहली, प्रमुख खाद्य मदों की विश्वव्यापी कीमतों में हाल ही की ऊर्ध्वमुखी प्रवृत्तियों का घरेलू कृषि क्षेत्र तथा समग्र समाष्टि आर्थिक एवं वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव हुआ है। यद्यपि पिछले वर्षों में समग्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश 1980-81 के लगभग 38 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2006-07 में 20 प्रतिशत से भी कम हो गया है, तथापि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने का क्रम जारी है। कृषि पर आश्रित जनसंख्या का अनुपात लगभग 60 प्रतिशत के रूप में विशाल बना हुआ है। हालांकि, 1990 वाले दशक के मध्यकाल से कृषि क्षेत्र की वृद्धि कम और उतार-चढ़ाव वाली रही है। कृषि उत्पादन में उतार-चढ़ाव का प्रभाव न केवल समग्र वृद्धि, अपितु जैसा कि 2006-07 के अनुभव से विस्तृत रूप से पता चलता है, मुद्रास्फीति को कम एवं स्थिर रखे जाने पर भी पड़ा है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा, गरीबी उपशमन, मूल्य स्थिरता, समग्र रूप से समावेशक वृद्धि तथा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की वृद्धि की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र की प्रवर्धित वृद्धि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण मौसम एवं मूल्य जोखिम को ध्यान में रखते हुए विपत्तिग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने के साथ-साथ उत्पादन की कुशलता बढ़ाने के लिए उपयुक्त जोखिम न्यूनीकरण नीतियां लागू की जानी आवश्यक होंगी। छोटी और खंडित कृषि जोतों को ध्यान में रखते हुए कृषिक गतिविधियों पर आश्रित जनसंख्या को भविष्य में अधिकाधिक रूप से कृष्येतर आय के स्रोतों पर निर्भर करना होगा। इस प्रकार मुर्गीपालन, खाद्य प्रसंस्करण और अन्य ग्रामीण उद्योगों जैसी गतिविधियों की ओर विशाखन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा।

दूसरी, आधुनिक आधारभूत सुविधा का अभाव और कुशल जनशक्ति की कमी वृद्धि के मार्ग के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अवरोध हैं। उद्योग को समृद्ध बनाने के लिए एक समर्थक परिवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यमान आधारभूत सुविधाओं, विशेषतः सड़कों, पत्तनों (बंदरगाहों) और बिजली, का संवर्धन अत्यावश्यक है। अब तक आधारभूत सुविधाओं में मिश्रित प्रगति हुई है। देश में बढ़ती चल (मोबाइल) टेलीफोन की प्रवृत्ति से यथा प्रतिबिंबित दूरसंचार क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण प्रगति परिलक्षित होती है। रेलवे और पत्तनों में भी कुछ सुधार परिलक्षित हुआ है। हालांकि, बिजली, कोयला, जल, सड़क, शहरी आधारभूत सुविधा और ग्रामीण आधारभूत सुविधा जैसे अन्य क्षेत्रों में यह प्रगति पर्याप्त से कम ही बनी हुई है। कोयले का सुरक्षित भंडार मौजूद होने के बावजूद - संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद विश्व के तीसरे सबसे बड़े देश - भारत को कोयले की अपर्याप्त धरेलू आपूर्ति और कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खनन वृद्धि में बढ़ोत्तरी लाने और औद्योगिक वृद्धि से संबंधित रुकावटों से छुटकारा पाने के लिए खनन क्षेत्र में और सुधार लाने आवश्यक होंगे। अधिक बिजली उत्पादन के लिए आश्वस्त ईंधन आपूर्ति की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कोयले की मांग के निकट अतीत की तुलना में महत्त्वपूर्ण रूप से अधिक होने की आशा है। पुनः शहरी आधारभूत सुविधा वृद्धि प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण तत्व होती है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि शहरी संकुलों के आकार में वृद्धि भारी उत्पादकता अभिलाभों से जुड़ी होती है। शहरों के प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण से सम्पूर्ण देश में शहरी आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा सकेगा।

तीसरी, सेवा क्षेत्र के प्रभावशाली कार्य-निष्पादन का कारण व्यापक रूप से कुशल एवं सस्ते श्रम की उपलब्धता थी। हालांकि, सेवा और विनिर्माण गतिविधियों में निरंतर त्वरण के फलस्वरूप अच्छी गुणवत्ता वाले कुशल श्रम की आपूर्ति पर आरंभिक

दबाव पड़ रहा है। जहां देश की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल उसे जनशक्ति की उपलब्धता की दृष्टि से अनुकूल रूप से प्रस्तुत करती है, वहीं उभरती प्रतिभा की आपूर्ति में कमी की रिपोर्टें भी प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक विकसित देशों में 40-50 प्रतिशत की तुलना में देश में संबंधित वय-समूह के केवल 10 प्रतिशत लोग ही उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश ले रहे हैं। माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के आधे से भी कम विद्यार्थी महाविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रयत्नशील रहते हैं। इसके अलावा, देश के कतिपय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता कुशल व्यावसायिकों की उभरती मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्तर से कम पड़ती है। जनसांख्यिक लाभांश से लाभ उठाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार एवं सुधार की तात्कालिक आधार पर आवश्यकता होगी।

चौथी, सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्ययों का पुनर्पूर्ववर्तीकरण तथा सरकार की परिचालनात्मक कुशलता में सुधार आवश्यक है। सामाजिक सेवाओं पर होने वाले अपेक्षाकृत अधिक सार्वजनिक व्ययों के साथ ही गुणवत्ता पर ध्यान संकेन्द्रण से सामाजिक आधारभूत सुविधा बढ़ेगी तथा उत्पादकता अभिलाभ प्राप्त होंगे। वर्तमान वृद्धि संवेग को टिकाऊ आधार पर सुदृढ़ किए जाने के लिए क्षमता निर्माण में और उन सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में महत्त्वपूर्ण अभिवृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, जो निजी क्षेत्र द्वारा नहीं प्रदान की जा सकतीं। राजकोषीय सशक्तीकरण से आधारभूत सुविधा एवं सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्ययों को बढ़ाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय उपलब्ध होंगे, जिसका धरेलू उत्पादकता, वृद्धि और रोजगार पर लाभकारी प्रभाव होगा।

अंतिम, बढ़ती ऋण मांग को पूरा करने के लिए बैंकों को उनके जमा आधार को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। विशेष रूप से बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय रूप से बहिष्कृत अधिक से अधिक लोगों को अपने

वलय में लाएं। कम आय वाले गृहस्थों की सहायता करने के अलावा, यह वित्तीय गहनता को सुदृढ़ बनाने में भी सहायक होगा तथा बैंकों को ऋण विस्तारित करने और उच्च आर्थिक वृद्धि को स्थिर रखने हेतु आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध कराएगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमात्रीकरणीय और गैर-प्रमात्रीकरणीय दोनों ही प्रकार की कुछेक अन्तर्निहित शक्तियां हैं, जो भावी चुनौतियों का सामना करने में सहायक होंगी। जिनका मैंने इसके पूर्व संकेत किया है उन प्रमात्रीकरणीय शक्तियों के अलावा, मेरे विचार से कतिपय सहजता से प्रमात्रीकृत न की जा सकने वाली शक्तियां भी हैं, जो भारत के पास मौजूद हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्नातकों का एक विशाल समूह और लाखों ऐसे लोग जो अंग्रेजी भाषा से भली भांति परिचित हैं, शक्ति के कुछेक स्रोत हैं। भारत में कई प्रकार की भाषाओं की जानकारी लोगों को बहु-सांस्कृतिक स्थितियों के बेहतर ढंग से अनुकूलन हेतु तैयार कर देती है, जिससे उनके लिए किसी अंतरराष्ट्रीय परिवेश को अपना लेना सहज हो जाता है। विश्व के सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र के रूप में स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व ज्यादतियों के विरुद्ध कुछ स्तर तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा सभी स्तरों पर सरकारों को अन्यथा की बजाय अधिक जवाबदेह बनाता है। महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु कई राज्यों द्वारा की गई पहलकदमियां प्रभावशाली हैं, जिनसे उन्हें अपने अधिकारों की प्रतिरक्षा करने तथा अधिकाधिक आत्म-सम्मान प्राप्त करने एवं अपने व्यक्तिगत जीवन एवं सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण रखने में सहायता प्राप्त होती है। केन्द्र में तथा कई राज्यों में होने वाले आवधिक चुनावों और गठबंधन के मंत्रिमंडलों के बावजूद राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता भारत में राजनीतिक वातावरण की विशेषता कही जा सकती है।

आगामी कुछेक दशकों के लिए भारत में “जनसांख्यिकीय लाभांश” को एक लाभ के रूप में देखा जाता है बशर्ते इस लाभांश को भुनाने के लिए कौशल उन्नयन एवं स्वस्थ अभिशासन की प्रभावी व्यवस्थाओं जैसी पूर्वापेक्षाओं को पूरा किया जाए। कारोबारी परिवेश की दृष्टि से अर्थव्यवस्था को बाजार उन्मुख बनाए जाने के साथ ही प्रभावशाली वृद्धि नींव जमाने से ले कर भव्य भवन खड़ा करने का कार्य सिद्ध हुई है। यह प्रवृत्ति संभवतः व्यावसायिकता से सराबोर और विश्वव्यापी स्तर पर स्पर्धात्मक बनने के इच्छुक पहले से ही विशाल एवं वृद्धिशील भारतीय उद्यमी वर्ग की नवोन्मेष के प्रति अभिरुचि का परिचायक है।

निष्कर्ष के तौर पर भारत में आगे बढ़ने का एक निर्णायक कारक होगा अभिशासन में सुधार, जो राज्य द्वारा उसके प्रमुख कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं न्यायोचित ढंग से संपादित करने हेतु उसकी क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। सरकारी संस्थाओं को सशक्त बनाते हुए अभिशासन की गुणवत्ता बढ़ाने में व्यावसायिक समाज को महत्वपूर्ण जोखिम उठाना होगा, क्योंकि अच्छा अभिशासन केवल तभी सफल हो सकता है, जब सार्वजनिक संस्थाएं न्यायसंगत एवं कुशल ढंग से कार्य करें।

सारणी 1 : भारत में वृद्धि एवं मुद्रास्फीति एक ऐतिहासिक रिकार्ड

अवधि (औसत)	(प्रतिशत)	
	सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर	शोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर
1951-52 से 1959-60 तक	3.6	1.2
1960-61 से 1969-70 तक	4.0	6.4
1970-71 से 1979-80 तक	2.9	9.0
1980-81 से 1990-91 तक	5.6	8.2
1991-92 (संकट का वर्ष)	1.4	13.7
1992-93 से 1999-00 तक	6.3	7.2
2000-01 से 2006-07 तक	6.9	5.1

सारणी 2 : भारत : चुनिंदा आर्थिक संकेतक
(राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है)

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
वास्तविक क्षेत्र							
1. सकल घरेलू उत्पाद, सांकेतिक, बिलियन अमेरिकी डॉलर*	460	478	508	602	696	806	911
2. सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन	4.4	5.8	3.8	8.5	7.5	9.0	9.4
3. प्रति व्यक्ति आय, अमेरिकी डॉलर #	455	461	473	543	618	712	797
4. उद्योग का सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन	6.4	2.7	7.1	7.4	9.8	9.6	10.9
5. सेवा सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन	5.7	7.2	7.4	8.5	9.6	9.8	11.0
6. बचत दर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	23.7	23.5	26.4	29.7	31.1	32.4	-
7. निवेश दर, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	24.3	22.9	25.2	28.0	31.5	33.8	-
मुद्रा, मूल्य, ऋण							
8. व्यापक मुद्रा (एम ³) मार्च के अंत में, वर्षानुवर्ष प्रतिशत परिवर्तन	16.8	14.1	12.7 @	16.7	12.1 @	17.0 \$	21.3
9. व्यापक मुद्रा (एम ³), मार्च के अंत में सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	62.5	65.7	69.9	72.5	72.0	76.5	80.2
10. थोक मूल्य सूचकांक, मार्च के अंत में, वर्षानुवर्ष प्रतिशत परिवर्तन	4.9	1.6	6.5	4.6	5.1	4.1	5.9
11. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कामगार, मार्च के अंत में, वर्षानुवर्ष प्रतिशत परिवर्तन	2.5	5.2	4.1	3.5	4.2	4.9	6.7
12. वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण, मार्च के अंत में, सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	32.3	33.3	36.6	36.7	40.9	47.5	51.5
13. गैर-खाद्य ऋण, मार्च के अंत में, वर्षानुवर्ष प्रतिशत परिवर्तन	14.9	13.6	18.6	18.4	27.5 @	31.8 \$	28.4
राजकोषीय क्षेत्र							
14. केन्द्र का सकल राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	5.7	6.2	5.9	4.5	4.0	4.1	3.5
15. केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित सकल राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत	9.5	9.9	9.6	8.5	7.5	6.7	6.4
16. सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सम्मिलित ऋण, प्रतिशत	70.8	76.4	81.0	81.6	82.5	80.5	77.0
विदेशी क्षेत्र							
17. माल का निर्यात, भुगतान संतुलन, बिलियन अमेरिकी डॉलर	45.4	44.7	53.8	66.3	85.2	105.2	127.1
18. माल का आयात, भुगतान संतुलन, बिलियन अमेरिकी डॉलर	57.9	56.3	64.5	80.0	118.9	157.0	192.0
19. पण्य व्यापार घाटा, भुगतान संतुलन, बिलियन अमेरिकी डॉलर	12.5	11.6	10.7	13.7	33.7	51.8	64.9
20. चालू खाते का शेष (+अधिशेष/-घाटा) बिलियन अमेरिकी डॉलर	-2.7	3.4	6.3	14.1	-2.5	-9.2	-9.6
21. चालू खाते का शेष (+अधिशेषय/-घाटा) सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	-0.6	0.7	1.2	2.3	-0.4	-1.1	-1.1
22. निवल पूंजी अंतर्वाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	8.8	8.6	10.8	16.7	28.0	23.4	44.9
23. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	4.0	6.1	5.0	4.3	6.0	7.7	19.4
24. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश बहिर्वाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	0.8	1.4	1.8	1.9	2.3	2.9	11.0
25. निवल पोर्टफोलियो प्रवाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	2.6	2.0	0.9	11.4	9.3	12.5	7.1
26. निवल विदेशी वाणिज्यिक उधार अंतर्वाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	4.3	-1.6	-1.7	-2.9	5.2	2.7	16.1
27. निवल अनिवासी भारतीय अंतर्वाह, बिलियन अमेरिकी डॉलर	2.3	2.8	3.0	3.6	-1.0	2.8	3.9
28. अंतरराष्ट्रीय आरक्षित निधि, मार्च के अंत में, बिलियन अमेरिकी डॉलर	42.3	54.1	76.1	113.0	141.5	151.6	199.2
29. ऋण की तुलना में आरक्षित निधि, प्रतिशत	41.7	54.7	72.5	101.2	114.0	118.8	127.1
30. खुलापन, माल एवं सेवाओं का व्यापार, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में	29.2	27.6	30.7	31.5	39.5	44.8	49.2
31. कुल विदेशी ऋण, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	22.5	21.1	20.3	17.8	17.4	16.0	16.6
32. विनियम दर, प्रति अमेरिकी डॉलर रुपया, वित्तीय वर्ष का औसत	45.7	47.7	48.4	45.9	44.9	44.3	45.3
33. वास्तविक रूप से प्रभावी विनियम दर, प्रतिशत परिवर्तन	5.3	-0.1	-4.9	1.5	2.6	5.4	-1.7

टिप्पणी: - : लागू नहीं।

* : सकल घरेलू उत्पाद को वित्तीय वर्ष के दौरान वर्तमान बाजार मूल्य पर औसत विनियम दर द्वारा विभाजित करते हुए परिकल्पित।

: प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस से उद्धृत वार्षिक आधार पर है।

@ : बैंकिंग क्षेत्र में हुए विलयन और संपरिवर्तन हेतु समायोजित। \$: 1 अप्रैल 2005 की स्थिति से भिन्नता।

स्रोत : वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष; विश्वव्यापी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष; वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, विश्व बैंक

**सारणी 3 : वित्तीय क्षेत्र के संकेतक
(राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है)**

संकेतक	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अ)
1. बैंकिंग क्षेत्र की आस्तियां, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	67.1	73.3	75.3	77.6	82.8	86.9	-
2. अनुसूचित वाणिज्य बैंक (एससीबी), जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी का अनुपात (सीआरएआर), प्रतिशत	11.4	12.0	12.7	12.9	12.8	12.3	12.3
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - बैंक ऋण-जमा अनुपात, प्रतिशत	53.1	53.4	56.9	55.9	64.7	71.5	74.0
4. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल लाभ, कुल आस्तियों का प्रतिशत	0.49	0.75	1.01	1.13	0.89	0.88	-
5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के सकल अग्रिमों की तुलना में उनकी सकल अनर्जक आस्तियां, प्रतिशत	11.4	10.4	8.8	7.2	5.2	3.5	2.7
6. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवल अग्रिमों की तुलना में उनकी निवल अनर्जक आस्तियां, प्रतिशत	6.2	5.5	4.0	2.8	2.0	1.3	1.1
7. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल आस्तियों की तुलना में उनकी सकल अनर्जक आस्तियां, प्रतिशत	4.9	4.6	4.0	3.3	2.5	1.9	-
8. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के परिचालन व्यय, कुल आस्तियों का प्रतिशत	2.64	2.19	2.24	2.21	2.13	2.11	-
9. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का निवल ब्याज मार्जिन, कुल आस्तियों का प्रतिशत	2.85	2.57	2.77	2.88	2.83	2.78	-
10. ईक्विटी बाजार, बाजार पूंजीकरण, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	27.2	26.8	23.3	43.4	54.3	84.7	85.9
11. ईक्विटी बाजार, पण्यवर्त अनुपात, प्रतिशत @	409.3	134.0	162.9	133.4	97.7	78.9	81.8
12. विदेशी मुद्रा बाजार, पण्यवर्त, बिलियन अमरीकी डॉलर	1,387	1,421	1,560	2,118	2,892	4,413	5,219
13. रुपये की विनिमय दर, प्रति अमरीकी डॉलर, औसत	45.68	47.69	48.40	45.95	44.93	44.28	45.28

@ : पण्यवर्त अनुपात स्टॉक बाजार पूंजीकरण द्वारा विभाजित लेन-देन किए गए शेयरों के कुल मूल्य के बराबर है। अ : अनंतिम

टिप्पणी : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (एससीबी) से संबंधित 2006-07 के आंकड़ों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

**सारणी 4 : अल्पकालिक संभावनाएं
(राजकोषीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है)**

	अवधि*	2006-07	2007-08
वास्तविक क्षेत्र			
1. सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन @		9.6	9.3
(i) कृषि, वन एवं मत्स्य ग्रहण वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		2.8	3.8
(ii) उद्योग, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		10.6	10.6
खनन, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		3.7	3.2
विनिर्माण, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		12.3	11.9
बिजली, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		5.8	8.3
निर्माण, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		10.5	10.7
(iii) सेवाएं, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		11.7	10.6
व्यापार, होटल, रेस्तरां, परिवहन, भंडारण एवं संचार, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		12.4	12.0
वित्तीय, बीमा, स्थावर संपदा एवं कारोबारी सेवाएं, वास्तविक प्रतिशत परिवर्तन		10.8	11.0
सामुदायिक सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं, वास्तविक, प्रतिशत परिवर्तन		11.3	7.6
2. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (आइआइपी), प्रतिशत परिवर्तन	अप्रैल-अगस्त	11.0	9.8
3. आधारभूत सुविधा उद्योगों का सूचकांक, प्रतिशत परिवर्तन	अप्रैल-अगस्त	8.3	6.6
मूल्य			
4. थोक मूल्य सूचकांक, प्रतिशत परिवर्तन, 52 साप्ताहिक औसत	29 सितंबर के दिन	4.55	5.28
5. थोक मूल्य सूचकांक, प्रतिशत परिवर्तन, वर्षानुवर्ष @@	29 सितंबर के दिन	5.41	3.26
6. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, प्रतिशत परिवर्तन, वर्षानुवर्ष	अगस्त	6.3	7.3
मुद्रा एवं ऋण			
7. व्यापक मुद्रा (एम ³), वर्षानुवर्ष, प्रतिशत परिवर्तन @@@	28 सितंबर के दिन	19.0	21.0
8. आरक्षित मुद्रा, वर्षानुवर्ष, प्रतिशत परिवर्तन	5 अक्टूबर के दिन	16.6	25.8
9. खाद्येतर ऋण, वर्षानुवर्ष, प्रतिशत परिवर्तन @@@@	28 सितंबर के दिन	31.6	22.1
राजकोषीय			
10. सकल राजकोषीय घाटा, केन्द्रीय सरकार, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	बजट अनुमान	3.5 \$	3.3
11. राजस्व घाटा, केन्द्रीय सरकार, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में प्रतिशत	बजट अनुमान	1.9\$	1.5
विदेशी क्षेत्र			
12. पण्य निर्यात, बिलियन अमरीकी डॉलर	अप्रैल-अगस्त	50.3	59.4
13. पण्य निर्यात, प्रतिशत परिवर्तन	अप्रैल-अगस्त	27.1	18.2
14. पण्य आयात, बिलियन अमरीकी डॉलर	अप्रैल-अगस्त	70.2	92.0
15. पण्य आयात, प्रतिशत परिवर्तन	अप्रैल-अगस्त	20.6	31.0
16. पण्य व्यापार का घाटा, बिलियन अमरीकी डॉलर	अप्रैल-अगस्त	19.9	32.5
17. चालू खाते का शेष (+ अधिशेष/-घाटा), बिलियन अमरीकी डॉलर		-4.6	-4.7
18. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह, बिलियन अमरीकी डॉलर	अप्रैल-जुलाई	3.7	6.6
19. विदेशी संस्थागत निवेश अंतर्वाह, बिलियन अमरीकी डॉलर #	अप्रैल-सितंबर	-0.1	15.5
20. अनिवासी जमाराशियों का अंतर्वाह, बिलियन अमरीकी डॉलर #	अप्रैल-जुलाई	1.6	-0.1
21. विदेशी मुद्रा की आरक्षित राशि, बिलियन अमरीकी डॉलर	5 अक्टूबर के दिन	165.3	251.3
22. विदेशी ऋण, बिलियन अमरीकी डॉलर	जून के अंत में	133.5	165.4

* : जब तक अन्यथा उल्लेख न हो अवधि अप्रैल-जून की है। # : ऋणात्मक (-) अंक बहिर्वाह का संकेत करते हैं। \$: अनंतिम लेखे।

@ : भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2007-08 के लिए इसके लगभग 8.5 प्रतिशत होने का अनुमान करता है।

@@ : भारतीय रिजर्व बैंक इसे वर्ष 2007-08 में 5.0 प्रतिशत तक नियंत्रित रखने की आशा करता है।

@@@ : वर्ष 2007-08 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान 17.0-17.5 प्रतिशत का है।

@@@@ : वर्ष 2007-08 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमान 24-25 प्रतिशत का है।

सारणी 5 : मध्यावधिक संभावनाएं

चुनौतियां

- कृषि, यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में इसका अंश 20% से भी कम है, इस पर आश्रित जनसंख्या विशाल (लगभग 60 प्रतिशत) बनी हुई है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा, गरीबी उपशमन, मूल्य स्थिरता, समग्र रूप से व्यापक वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था की वृद्धि की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए कृषि क्षेत्र की प्रवर्धित वृद्धि महत्वपूर्ण है।
- आधुनिक आधारभूत सुविधा का अभाव और कुशल जनशक्ति की कमी वृद्धि के मार्ग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवरोध हैं। इस उद्योग को समृद्ध बनाने के लिए एक समर्थक परिवेश उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्यमान आधारभूत सुविधाओं, विशेषकर सड़कों, पत्तनों (बंदरगाहों) और बिजली में संवर्धन अत्यावश्यक है।
- जनसांख्यिक लाभांश से लाभ उठाने के उद्देश्य से शिक्षा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार एवं सुधार की तात्कालिक आधार पर आवश्यकता होगी।
- अपेक्षाकृत अधिक पूंजी परिव्ययों के साथ ही सामाजिक क्षेत्रों पर होने वाले व्ययों के पुनर्पूर्ववर्तीकरण से सरकार की परिचालनात्मक कुशलता को प्रतिबंधित किए बिना राजकोषीय अनुशासन को संवर्धन प्राप्त होगा। राजकोषीय सशक्तीकरण से आधारभूत सुविधा एवं सामाजिक क्षेत्र पर होने वाले व्ययों को बढ़ाने हेतु अपेक्षाकृत अधिक परिव्यय उपलब्ध होंगे, जिसका घरेलू उत्पादकता, वृद्धि और रोजगार पर लाभकारी प्रभाव होगा। इस प्रकार, यह जरूरी है कि राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता के महत्त्व पर बल दिया जाए।
- ऋण की बढ़ती मांग को पूरा करने और अधिक आर्थिक वृद्धि को स्थिर रखने के लिए बैंकों को उनके जमा आधार को व्यापक बनाना होगा। बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे वित्तीय रूप से बहिष्कृत अधिक से अधिक लोगों को अपने वलय में लाएं, जिससे कम आय वाले गृहस्थों को सहायता प्राप्त होगी तथा वित्तीय गहनता को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

शक्तियां

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्नातकों का एक विशाल समूह और लाखों ऐसे लोग जो अंग्रेजी भाषा से भलीभांति परिचित हैं।
- कई भाषाओं की जानकारी बहु सांस्कृतिक स्थितियों के प्रति अनुकूलन बेहतर बना देती है, जिससे उनके लिए किसी अंतरराष्ट्रीय परिवेश को अपना लेना सहज हो जाता है।
- विश्व के सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र के रूप में स्वतंत्र प्रेस का अस्तित्व ज्यादतियों के विरुद्ध कुछ स्तर तक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराता है तथा सरकारों को अन्यथा की बजाय अधिक जवाबदेह बनाता है।
- महिलाओं का सशक्तीकरण जिससे उन्हें उनके अधिकारों की प्रतिरक्षा करने और अधिकाधिक आत्म-सम्मान प्राप्त करने एवं उनके व्यक्तिगत जीवन और सामाजिक संबंधों पर नियंत्रण रखने में सहायता प्राप्त होती है।
- गठबंधन मंत्रिमंडलों और आवधिक चुनावों के बावजूद राजनीतिक वातावरण की विशेषता है राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता।
- “जनसांख्यिकीय लाभांश” को लाभ के रूप में देखा जाता है बशर्ते उससे लाभ उठाने के लिए कौशल उन्नयन एवं स्वस्थ अभिशासन जैसी पूर्वापेक्षाओं को पूरा किया जाए।
- कारोबारी परिवेश की दृष्टि से नवोन्मेष के प्रति अभिरुचि रखने वाले, व्यावसायिकता से ओतप्रोत, विश्वव्यापी स्तर पर स्पर्धात्मक बनने के इच्छुक अत्यधिक व्यापक आधार वाले बढ़ते उद्यमशील वर्ग का अभ्युदय।

निर्णायक कारक

- राज्य की क्षमता को सुदृढ़ करना तथा उसे उसके प्रमुख कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं न्यायोचित ढंग से करने में समर्थ बनाना।